

श्रीमती इन्दिरा गान्धी के समय विश्व के प्रमुख देशों के साथ सम्बन्ध (सन् 1980 से सन् 1984 तक)

डॉ० दिलबाग सिंह बिसला

निर्देशक राजीव गांधी शोध एवं अध्ययन केन्द्र, आर्यनज संस्थान, रतीबाड़, भोपाल

प्रस्तावना

श्रीमती इन्दिरा गान्धी सन् 1980 में पुनः प्रधानमंत्री बनी। उन्होंने सन् 1977 में विदेशनीति जहां पर छोड़ी थी वहीं से लेकर विदेशनीति का विकास किया। उन्होंने जनता पार्टी के आदर्शवाद को त्याग, फिर से यथार्थवाद को अपना लिया, ताकि भारत दक्षिण एशिया की सर्वोच्च शक्ति बने और इसे मान्यता मिलनी ही चाहिये, जिससे इस क्षेत्र में शान्ति सुरक्षा की स्थापना हो सके। इस युग में उन्होंने गुटनिरपेक्षता की तरफ अधिक ध्यान दिया। उस में तीव्रता और प्रखरता का संचार किया। विदेशनीति को और व्यावहारिक बनाया तथा तीसरी दुनिया की आर्थिक व राजनैतिक आजादी के लिए कारगर कार्यवाही पर बल दिया। साथ ही साथ शोषण करने वाली शक्तियों की आलोचना की। संयुक्त राष्ट्र संघ और गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की आवाज को बुलन्द किया जिससे नये विश्व की रचना उनके अनुकूल हो सके।

इस प्रकार मार्च, 1983 में गुट निरपेक्ष आन्दोलन का नेतृत्व ग्रहण करने के साथ श्रीमती इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रीय नेताओं की पहली श्रेणी में आ गई थी। भारत की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और राजनयिक प्रभाव में वृद्धि हुई और उनके जीवन पर्यन्त कोई कमी नहीं आई।¹ आन्दोलन को गत्यात्मकता तथा सम्बद्धता प्रदान करने में सफल रही। निःशस्त्रीकरण व परमाणु निःशस्त्रीकरण के पक्ष में विश्व जनमत को जागृत कर विश्व को उसके महत्व को समझाया।

सातवां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन 7 मार्च से लेकर 11 मार्च, 1983 तक नई दिल्ली में आयोजित हुआ। शिखर सम्मेलन के सामने विशिष्ट रूप से दो प्रश्न विचारणीय थे : परमाणु युद्ध तथा शस्त्रों की होड़ पर किस तरह काबू पाया जाये ? विश्व में अधिक समान आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार कायम की जा सके ? अपने भाषण में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने कहा था कि, "शान्ति खतरे में है, मानवता को शस्त्रों की निरन्तर बढ़ती दौड़ से खतरा है। विकासशील देशों के बीच संसाधनों का समान तथा सुसंगत विभाजन होना चाहिए।" इसमें ईरान तथा ईराक से गम्भीरतापूर्वक प्रार्थना की गई थी कि वे युद्ध समाप्त कर दें। 'नाम' के निर्गट तत्व पर अपना अटूट विश्वास प्रकट करते हुए घोषणा में यह विश्वास दिलाया गया था कि 'नाम' संयुक्त राष्ट्र संघ की सीमा में काम करता रहेगा, क्योंकि हम एक ही नाव के सवार हैं। अफगानिस्तान तथा कम्पूचिया का नाम लिए बिना संदेश में सभी राष्ट्रों से यह आह्वान किया गया था कि वे एक दूसरे की अखण्डता, स्वतंत्रता तथा प्रभुसत्ता को निश्चित बनाए रखें।²

श्रीमती गान्धी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के 38वें अधिवेशन में कहा था कि, "दोनों ही महाशक्तियों को शीत युद्ध के युग की समाप्ति करने, सभी परमाणु राज्यों से परमाणु शस्त्र दौड़ को समाप्त करने, सभी राष्ट्रों से निःशस्त्रीकरण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सर्वसम्मति जुटाने के लिए एक दूसरे के निकट आने तथा विकसित राष्ट्रों से नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के विषय पर तुरन्त ही उत्तर-दक्षिण वार्ता करने के लिए आगे आने की प्रार्थना की थी।"³ यह निश्चय ही निःशस्त्रीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के लिए अन्तर्राष्ट्रीय चेतना जगाने की ओर निर्भीक उपक्रमण था।⁴

दक्षिण-दक्षिण सहयोग, शांति, मैत्री तथा सहयोग को बढ़ावा देने तथा अविकसित देशों की आर्थिक, औद्योगिक तथा तकनीकी प्रक्रिया को तेज करने के लिए भारत ने दक्षिण-दक्षिण सहयोग को प्राथमिकता तथा अत्यधिक महत्व देने का निर्णय किया। श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने विशिष्ट रूप से सामान्यता तीसरे विश्व के देशों तथा विशेषतया गुट-निरपेक्ष देशों के मध्य क्षेत्रीय सहयोग में वृद्धि के लिए कई कदम उठाए।⁵

मई, 1984 को श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने पांच अन्य राष्ट्रों के साथ मिलकर परमाणु शक्तियों अर्थात् अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन तथा फ्रांस को परमाणु अस्त्रों-शस्त्रों के उत्पादन को रोक देने के लिए एक संयुक्त प्रार्थना की थी।⁶

भारत-अमेरिका सम्बन्ध

जनवरी, 1980 को श्रीमती इन्दिरा गान्धी पुनः भारत की प्रधानमंत्री बनीं। इस समय रीगन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने अमेरिका तथा भारत के सम्बन्धों को अच्छा बनाने का प्रयास किया तथापि सम्बन्ध पहले की तरह मैत्रीपूर्ण तथा सहयोगात्मक, परन्तु माधुर्य, गहराई तथा उत्साह से रहित ही बने रहे। जिसके कारण थे अफगानिस्तान संकट, पाकिस्तान को अत्याधिक आधुनिक शस्त्र तथा युद्ध विमानों की आपूर्ति, डियागो गार्शिया की समस्या, कम्पूचिया को मान्यता देने पर मतभेद तथा भारत की परमाणु नीति के प्रति दोनों देशों के बीच अन्तर के कारण सम्बन्धों के अच्छे बनने के रास्ते में बड़ी रुकावट बनी रही। इसके अतिरिक्त नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था तथा उत्तर और दक्षिण के बीच आर्थिक सम्बन्धों की समस्या पर भारत तथा अमेरिका में आपसी मतभेद बना रहा। सन् 1981 में श्रीमती इन्दिरा गान्धी व रीगन के बीच कानकून में वार्ता हुई। इससे दोनों देशों के बीच में बदलाव की नई प्रक्रिया को 'सहयोग की नई खोज' की संज्ञा दी गई।⁷ वहीं कुछ विद्वानों ने इसे दोनों देशों के सम्बन्धों की नई दिशा बताई थी।⁸

सन् 1982 में श्रीमती इन्दिरा गान्धी अमेरिका गई थी 9 तथा राष्ट्रपति रीगन के साथ महत्वपूर्ण बातचीत की थी। दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे के दृष्टिकोण को अच्छी तरह समझा और सम्बन्धों को सुधारने के लिए प्रयास करना स्वीकार किया था।¹⁰ इस यात्रा के दौरान भारत की यूरेनियम की आपूर्ति की समस्या को भी बुद्धिमानी से सुलझा लिया गया।¹¹ नए समझौते के अनुसार अमेरिका के स्थान पर फ्रांस ने पुष्ट यूरेनियम देना स्वीकार कर लिया था। इससे दोनों देशों के बीच की एक मुख्य रुकावट दूर हो गई थी तथा दोनों देशों के बीच पहले से अधिक अच्छे सहयोग के अवसर दिखाई देने लगे थे।¹²

सन् 1982 से सन् 1984 तक के काल में वास्तव में सम्बन्धों में कोई विशेष सुधार दृष्टिगोचर नहीं हुआ। अमेरिका का पाकिस्तान को अत्याधुनिक शस्त्रों को देते रहने का निर्णय,¹³ अमेरिका की नवीन अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के प्रति उदासीनता, अमेरिका का अधिक से अधिक आधुनिक शस्त्रों का विकास करने तथा उन्हें लगाने का निर्णय, अमेरिका का अपनी भूमि पर भारत विरोधी

उग्रवाद को नियन्त्रण कर सकने की समस्या के प्रति असहायक व्यवहार, हिन्द महासागर में, विशेषतया खाड़ी के क्षेत्र में, सैनिक गतिविधियां शुरू करने का अमेरिकी निर्णय¹⁴ तथा भारत की सोवियत संघ के साथ बढ़ती मैत्री, इन सभी ने मिलकर भारत तथा अमेरिका के सम्बन्ध को विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित रखा। मई 1984 में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जार्ज बुश ने भारत की यात्रा की थी। कुछ मुद्दों पर बुश ने माना था कि दोनों देशों के बीच मतभेद हैं¹⁵ फिर भी आर्थिक, सांस्कृतिक वैज्ञानिक व तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा।¹⁶

भारत-सोवियत सम्बन्ध

जनवरी, 1980 के चुनावों में भारत में श्रीमती इन्दिरा गांधी सत्ता में वापिस आ गई तथा भारत में सरकार के इस परिवर्तन ने सोवियत संघ और भारत में इस आशा को जगा दिया था कि वे सन् 1977 से पहले वाले मैत्रीपूर्ण तथा गहरे सम्बन्ध बना लेंगे। सोवियत संघ का यह आशावाद ठीक सिद्ध हुआ। जब संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत को यह निर्देश दिया गया, कि वह अफगानिस्तान पर अपनी स्थिति के विषय में संशोधन कर ले। अफगानिस्तान की गम्भीर स्थिति पर गहरी चिन्ता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान में केवल सोवियत संघ ने ही हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि कुछ अन्य बाहरी ताकतें भी कई वर्षों से इस देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही हैं।¹⁷ सोवियत संघ की अफगानिस्तान कार्यवाही के पूर्ण विरोध के स्थान पर भारत की सीमित आलोचना से सोवियत संघ ने सन्तोष व्यक्त किया था। भारत तथा सोवियत संघ दोनों देशों के बीच सहयोग को सुदृढ़ करने के प्रयत्न जारी रहे। जून, 1980 में तत्कालीन विदेशमन्त्री श्री नरसिम्हा राव ने सोवियत संघ का दौरा किया था तथा सोवियत नेताओं से बातचीत की थी। राष्ट्रपति ब्रेजनेव के निमन्त्रण पर तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने सितम्बर-अक्टूबर 1980 में सोवियत संघ का सरकारी दौरा किया था।¹⁸ इस दौर के दौरान भारत तथा सोवियत सम्बन्धों की समीक्षा की गई तथा विकास पर सन्तोष व्यक्त किया गया था।

इसी प्रकार दिसम्बर, 1980 में सोवियत राष्ट्रपति श्री ब्रेजनेव ने भारत का दौरा किया था तथा एक बार फिर भारत तथा सोवियत संघ के बीच तेजी से विकसित होते हुए सहयोग की सराहना की गई।¹⁹ दोनों देशों के बीच मित्रता सुदृढ़ करने के अतिरिक्त इस दौर के दौरान कुछ द्विपक्षीय समझौते भी किए गए, जैसे 1981 से 1985 तक के लिए व्यापार समझौता, सन 1981 तथा सन 1982 के वर्षों के लिए सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा शैक्षणिक आदान-प्रदान समझौता आदि।²⁰ ये समझौते भारत तथा सोवियत संघ के बीच विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते सहयोगात्मक सम्बन्धों की नीति के अनुरूप ही थे।

इस प्रकार सन् 1980-1984 तक की अवधि में भारत तथा सोवियत संघ के सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण तथा सहयोगात्मक बने रहे। टी.एन. कौल ने लिखा है कि, भारत तथा सोवियत संघ के पुराने सम्बन्धों के स्वरूप का बड़ी गहराई से तथा व्यवस्थापूर्वक विश्लेषण किया तथा यह भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच सम्बन्ध और घनिष्ठ, सौहार्दपूर्ण तथा व्यवस्थित ढंग से सहयोगात्मक होंगे।²¹

भारत-चीन सम्बन्ध

कांग्रेस (ई.) फिर सत्ता में आ गई। इस परिवर्तन से एक बार फिर भारत-सोवियत विशेष सम्बन्धों के सम्भावित युग की वापसी हुई और चीन के साथ सम्बन्धों में चौकसी और नियन्त्रण की नीति की पुनः वापसी हुई। श्रीमती इंदिरा गांधी ने बिना समय गंवाए भारत-चीन सहयोग के विकास के लिए प्रयास करने शुरू कर

दिए।²² सन् 1980 से लेकर भारत तथा चीन अपने व्यापारिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धों को बनाए रखने तथा उनमें वृद्धि के निरन्तर प्रयास किये गये।²³ लेकिन दोनों देशों के राजनीतिक सम्बन्धों में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वियतनाम तथा कम्बूधिया के प्रति नीति भेद होने के कारण तथा सीमा विवाद के बने रहने के कारण, परिपक्वता और सूझ-बूझ की कमी विद्यमान रही। 2 फरवरी, 1983 को तीसरे दौर की अधिकारी स्तर की वार्ता बिना किसी सफलता के समाप्त हो गई थी।²⁴ इस समय यह ज्ञात हुआ था कि कुछ समय से चीन भारत में चल रहे भूमिगत नागा विद्रोहियों, मिजो विद्रोहियों या नक्सलवादियों का समर्थन नहीं कर रहा है और निकटता के सम्बन्ध स्थापित करने का इच्छुक है। परन्तु वार्ताओं से दोनों पक्ष अपने मतभेदों को कम करने में सफल नहीं हुए।²⁵ परन्तु शिक्षा के सम्भव वैज्ञानिक एवं प्राद्यौगिक विनियम का कार्यक्रम तैयार किया गया।²⁶ 15 अगस्त, 1984 को बीजिंग में भारत-चीन व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, दोनों देशों के बीच यह सन् 1976 से राजदूतों के आदान-प्रदान के बाद पहला सरकारी स्तर पर समझौता था।²⁷ चीन के उप-प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी के अन्तिम संस्कार में भाग लेने भारत आए थे।²⁸ लेकिन सीमा विवाद के कारण दोनों देशों के सम्बन्धों में मतभेद बना रहा।²⁹

भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध

15 सितम्बर, 1981 को एक प्रैस रिपोर्ट में पाकिस्तान द्वारा भारत के साथ तत्काल ही शिमला समझौते की भावना के अन्तर्गत अनाक्रमण तथा शक्ति प्रयोग न करने का परस्पर आश्वासन देने के उद्देश्य से बातचीत करने की इच्छा व्यक्त की गई। पाकिस्तान की पहल पर भारत ने इन मुद्दों पर विचार-विमर्श करने का निर्णय किया :

1. अनाक्रमण समझौते के मामले पर पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू की जाए।
2. पाकिस्तान के साथ अधिक सुदृढ़ आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी सम्पर्क बनाने के लिए सुदृढ़ आधार के रूप में एक शान्ति, मित्रता तथा सहयोग की व्यापक संधि का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए तथा
3. शिमला समझौते में निहित भावना के अनुसार ही भारत तथा पाकिस्तान के बीच व्यापारिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धों का विकास किया जाए।³⁰

इन उद्देश्यों के आधार पर भारत की सरकार ने सन् 1981 के अंतिम महीनों में पाकिस्तान के साथ खुलकर बातचीत शुरू की। परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच आने-जाने का एक सिलसिला शुरू हो गया। जून, 1982 में पाकिस्तान ने अनाक्रमण समझौते के प्रस्ताव के मसौदे को देखने तथा उस पर आगे बातचीत करने के लिए भारत को भेजा। अगस्त, 1982 में भारत के विदेश सचिव एम. के. रसगोत्रा ने पाकिस्तान का दौरा किया तथा वहां के विदेश सचिव नियाज ए. नायक तथा जनरल जिया के साथ महत्वपूर्ण बातचीत की थी। जनवरी, 1982 में दोनों देशों के विदेश सचिवों की नई दिल्ली में बैठक हुई तथा अनाक्रमण समझौते के मामले पर दोनों देशों में विचार विमर्श किया गया।

अगस्त 1982 में दोनों देशों के प्रतिनिधियों की बैठक पाकिस्तान के अनाक्रमण समझौते के प्रस्ताव तथा भारत के शांति, मैत्री तथा सहयोग की व्यापक संधि के प्रस्ताव पर खुली तथा मुक्त बातचीत हुई दोनों के प्रारूप में निम्न बातें थी:

1. युद्ध के रोकने तथा अनाक्रमण के लिए संयुक्त प्रतिबद्धता।
 2. भारत तथा पाकिस्तान के आपसी झगड़े नितान्त शान्तिपूर्ण संधियों द्वारा सुलझाना।
 3. भारत तथा पाकिस्तान के बीच अच्छे पड़ोसियों जैसे सम्बन्ध कायम करने की संयुक्त प्रतिबद्धता जैसे प्रस्ताव थे।
- भारत ने इसे कई कारणों से अपर्याप्त पाया। इसे शिमला समझौते

को कमजोर करने का प्रयत्न समझा गया तथा जिसका उद्देश्य ऐसी धारणाएँ व्यक्त करने के सिवाए कुछ नहीं था कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच के सम्बन्धों को सुदृढ़ किया जाए। इस मसौदे में दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय सम्बन्धों को सुदृढ़ करने के लिए कुछ भी नहीं था।³¹

भारत तथा पाकिस्तान के सम्बन्धों में वास्तविक परिवर्तन 1 नवम्बर, 1982 को उस समय आया जब प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी तथा जनरल जिआ ने अपनी बातचीत में, गैर राजनैतिक तथा असैनिक सम्बन्धों में विकास की देखभाल के लिए भारत तथा पाकिस्तान का एक संयुक्त पैनल बनाना स्वीकार किया। उन्होंने यह भी स्वीकार किया था कि दिसम्बर 1982 को अनाक्रमण समझौते तथा शांति और सहयोग की संधि के प्रस्तावों पर सचिव स्तरीय बातचीत पुनः आरम्भ की जाए। दिसम्बर, 1982 को दोनों देशों के विदेश सचिवों की दिल्ली में बैठक हुई जिसमें भारत-पाक संयुक्त आयोग के संगठन तथा कार्यों के लिए एक प्रारूप प्रस्तुत किया गया।³² उन्होंने भारत तथा पाकिस्तान द्वारा प्रस्तुत किए समझौते तथा शान्ति मैत्री तथा सहयोग की संधियों के प्रारूपों का आदान-प्रदान किया। जनवरी, 1983 में नटवर सिंह ने इस्लामाबाद का दौरा किया था तथा दोनों देशों के बीच आपसी सुझबूझ का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास किया था।³³ इस दौर का उद्देश्य गुटनिरपेक्षता की व्याख्या तथा अन्य राजनैतिक तथा सुरक्षा सम्बन्धी मामलों पर दोनों देशों के बीच उठे मतभेदों को कम करना था।

सन् 1983 में गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में जनरल जिआ भारत आये तथा देश को सहयोगात्मक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक सम्बन्धों का सुखद आरम्भ हुआ।³⁴ इसी दौरान मानव आयोग के सामने कश्मीर मुद्दा उठा तथा पंजाब को उग्रवादियों को सहायता व शरण देने के मामलों ने दोनों देशों के सम्बन्धों में खटास पैदा कर दी।

भारत-बंगलादेश सम्बन्ध

सन् 1980 में भारत-बंगलादेश के बीच सम्बन्धों में तनाव का कारण न्यू-मूर द्वीप को बंगलादेश द्वारा अपना अधिकार क्षेत्र बताना था। तत्कालीन विदेशमंत्री नरसिम्हाराव ने बंगलादेश की यात्रा की थी और इस समस्या को बातचीत से सुलझाने का प्रस्ताव रखा था। दोनों सरकारों ने अपने-अपने आंकड़े एक दूसरे को देने का प्रस्ताव भी किया था। 6 सितम्बर, 1981 को दिल्ली तथा ढाका से एक ही समय में जारी एक विज्ञप्ति में यह घोषणा की गई थी कि दोनों देश न्यू-मूर द्वीप के प्रश्न पर उत्पन्न हुए तनाव को कम कर पाने में सफल हुए हैं। भारत विरोधी गतिविधियाँ निरन्तर जारी हैं। सन् 1991, के बंगलादेश के चुनावों में भी यह तथ्य सामने आया। न्यू-मूर द्वीप का स्वामित्व झगड़े का कारण बना। जो इरशाद और श्रीमती इन्दिरा शिखर सम्मेलन की भावना के विरुद्ध था। चकमा शरणार्थियों की समस्या ने भी दोनों देशों के सम्बन्धों में उतेजना पैदा की, परन्तु 3 बीघा बंगलादेश को स्थायी पट्टे पर दे दिया गया।³⁵ सन् 1984 में बाड़ लगाने पर भी दोनों देशों में कटूता बढ़ी क्योंकि बंगलादेश राईफल ने मजदूरों पर गोलियाँ चला दी थी।³⁶

भारत-श्रीलंका सम्बन्ध

भारत-श्रीलंका ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक बंधनों में बंधे हैं। सभी क्षेत्रों में सहयोग और सौहार्द बना रहे। दोनों ही देश गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के हितों तथा तीसरे विश्व के अधिकारों की प्राप्ति के लिए और अच्छी तथा बड़ी भूमिका निभा रहे थे। दोनों ही हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाने के लिए वचनबद्ध थे। परन्तु तमिल समस्या दोनों के बीच तनाव का कारण बन गई थी। श्रीलंका द्वारा तमिल समस्या का सैनिक निदान दुःखदायी बन गया था। श्रीलंका की सेना ने तमिल विद्रोह को कुचलने की आड़ में व्यावहारिक रूप से सारे तमिलों के विरुद्ध जो अत्याचारों का सिलसिला शुरू किया

था उससे तमिल छापामारों के आक्रमणों तथा विघटनकारी गतिविधियों में वृद्धि हो गई। स्थिति गम्भीर रूप से बिगड़ गई। भारत पर इसका प्रभाव पहले तो पाक जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव के पैदा होने के रूप में पड़ा। जिसके परिणामस्वरूप लंका की नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों पर गोलीबारी की गई। भारत द्वारा भी भारतीय सीमा के अन्दर आने वाली श्रीलंका की नौकाओं को प्रतिकार स्वरूप पकड़ लिया गया। ऐसे तनावों के कारण भारत में बड़ी संख्या में तमिल शरणार्थियों को आने के लिए बाध्य होना पड़ा। इन शरणार्थियों को भारत ने मानवता के आधार पर आश्रय दिया। सन् 1981 व 1983 के तमिलों सिंगली दगों ने सन् 1958 व 1977 की पुनरावृत्ति ही नहीं की, बल्कि उसके घोर निराशावादी रूप का प्रदर्शन किया।³⁷ परन्तु जब जून, 1984 में राष्ट्रपति जयावर्द्धन भारत की यात्रा पर आये, तो भारत ने समस्या के समाधान की बात कही।³⁸ परन्तु श्रीलंका की अखण्डता के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने का वचन भी दिया था।³⁹

भारत-नेपाल सम्बन्ध

नवम्बर, 1980 में भारत के विदेशमंत्री श्री नरसिम्हाराव ने नेपाल की यात्रा की तथा वहां के प्रधानमंत्री श्री सूर्य बहादुर थापा तथा नेपाल के पंचायत मंत्री श्री नबराज सुबेदी से विभिन्न मामलों पर महत्वपूर्ण बातचीत की थी।⁴⁰ दिसम्बर, 1981 में राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी ने नेपाल की राजकीय यात्रा की थी।⁴¹ जुलाई, 1983 को देवी घाट जल विद्युत परियोजना के शुरु हो जाने से नेपाल के आर्थिक तथा औद्योगिक विकास के मार्ग में भारत की सहायता की प्रशंसा की गई।⁴² मई, 1982 को एक समझौते द्वारा भारत ने नेपाल को कई व्यापारिक तथा पारागमन सुविधाएं दीं।

भारत-भूटान सम्बन्ध

एक स्वतन्त्र देश के रूप में भूटान में धीरे-धीरे एक नये विश्वास तथा उत्साह का संचार हो रहा था। सार्क की सदस्यता तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भागीदारी से भूटान में नई जागृति का विकास हो रहा था। भारत को अपने इस पड़ोसी मित्र राज्य के साथ गहन रूप से मधुर तथा सहयोगी सम्बन्ध बनाए रखने के लिए निरन्तर प्रयत्न करते रहने की आवश्यकता है।

इंग्लैण्ड-भारत सम्बन्ध

8 मार्च, 1982 को लंदन में भारत महोत्सव मनाया गया। दोनों देशों के सांस्कृतिक सम्बन्धों के साथ-साथ राजनीतिक सम्बन्ध भी बढ़े। श्रीमती इन्दिरा गाँधी इंग्लैण्ड गई थी।⁴³

सन् 1982 में भारत ने एशिया खेलों का सफल आयोजन कर एशियाई देशों पर भारतीय अक्षमता व आत्म-निर्भरता का नया प्रभाव छोड़ा तथा खेलों के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के विकास का भारतीय विदेश नीति में यह एक नवीन तत्व था।⁴⁴ मार्च, 1983 में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन में 101 राष्ट्रों के भाग लेने से समस्त देशों में भारत की विश्व शान्ति, सौहार्द व सद्भावना बढ़ाने की दिशा में सक्रियता दिखाई तथा विश्व स्तर के नेता के रूप में श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रमुख रही।⁴⁵ फ्रांस से यूरेनियम की प्राप्ति के लिए नवम्बर, 1982 में समझौता भी उनकी एक बड़ी उपलब्धी थी।⁴⁶ क्योंकि तारापुर परमाणु बिजली घर के संचालन के लिए हमें यूरेनियम की बहुत जरूरत थी। इस प्रकार उनकी इस समय की विदेश नीति विश्व परिप्रेक्ष्य को देखते हुए सफल रही।⁴⁷

संदर्भ

1. इन्दिरा गांधी - पीपुल्स एण्ड प्रोब्लस, दिल्ली, 1983, पृ 7-8,
2. वही, पृ 193-96

3. वही, पृ0 429-33
4. विदेश मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट 1983-84
5. वही
6. वही
7. दिलीप मुखर्जी - "इण्डियाज रिलेशनस विद युनाटिड स्टेटस : ए न्यू सर्च फोर एकोमोडेशन, "पेज 197-214
8. सुरजीत मान सिंह-"न्यू डायरक्शनज इन इण्डो -यू0 एस0 रिलेशनस",1986 पेज 185-195
9. टाईम्स आफ इण्डिया , 27 जुलाई 1982 नई दिल्ली
10. वाहित हाउस -"बैकग्राउन्ड ब्रिफिंग पेपर आन दा विजिट आफ इन्दिरा गांधी," 26 जुलाई 1982
11. बी. एल. फड़िया -"इन्टरनैशनल पोलिटिक्स," पृ0 322
12. टाइम्स आफ इण्डिया, 14 जून 1982 नई दिल्ली।
13. आर. एस. यादव-"भारत की विदेश नीति: एक विश्लेषण," पृ0 120
14. बी. पी. गौतम - "इण्डियाज फोरन पौलिसी," पृ0 224
15. शीलाऔझा -"समयकालीन भारतीय विदेश नीति -भाग दो," पृ0 180
16. टाईम्स आफ इण्डिया, 18 मई 1984 नई दिल्ली
17. यू. आर. घई -" भारतीय विदेश नीति," पृ0 210
18. भारत सरकार विदेश मन्त्रालय, वार्षिक बजट 1980-81
19. टाईम्स आफ इण्डिया, 12 दिसम्बर 1980
20. देवेन्द्र कौशिक -"दा न्यू कोल्ड वार: दि सोवियत यूनियन एण्ड इश्टन यूरोप," नई दिल्ली 1985 पृ0 146
21. इण्डियन एक्सप्रेस 14 अप्रैल, 1982 नई दिल्ली।
22. टाईम्स आफ इण्डिया 3 फरवरी, 1983
23. इण्डियन एक्सप्रेस 21 जून, 1981
24. 24 ऐशियन रिकार्डर, 29 जुलाई - 4 अगस्त, 1980 पृ0 155-177
25. दी ट्रिब्यून 3 फरवरी, 1983 चण्डीगढ़।
26. जगत एस0 मेहता -"इण्डो -चाईना रिलेशन", पृ0 244-246
27. इण्डियन एक्सप्रेस, 16 अगस्त 1984 नई दिल्ली
28. टाईम्स आफ इण्डिया 2 नवम्बर, 1984 नई दिल्ली।
29. 29 शीला औझा, "भारतीय विदेश नीति," 2000 जयपुर पृ0 70
30. विदेश मंत्रालय, वार्षिक रिपोर्ट, 1981-1982
31. इण्डियन एक्सप्रेस, 22 नवम्बर, 1981 नई दिल्ली
32. टाईम्स आफ इण्डिया, 5 दिसम्बर 1982 नई दिल्ली
33. हिन्दुस्तान टाईम्स, 7 जनवरी 1985 नई दिल्ली
34. विदेश मंत्रालय, वार्षिक रिपोर्ट, 1982-83
35. फोरन अफेयर्स रिकोर्ड, अक्टूबर 1982
36. हिन्दुस्तान टाईम्स, 22 अप्रैल 1984 नई दिल्ली।
37. गुरचरण सिंह, "दी एथेनिक प्रोब्लम इल श्रीलंका एण्ड इण्डिया, एटेम्पट्स एट मिडऐसन," नई दिल्ली 1985, पृ0 124
38. टाईम्स आफ इण्डिया, 1 जुलाई 1984 नई दिल्ली।
39. हिन्दुस्तान टाईम्स 2 जुलाई, 1984 नई दिल्ली।
40. आर. एस. यादव, "भारत की विदेश नीति-एक विश्लेषण," पृ0 146
41. मानिक लाल गुप्ता-"भारतीय विदेश नीति और निकटतम पड़ोसी राष्ट्र," नई दिल्ली 1992, पृ0 62
42. रमेश ठाकुर -"दा पौलिटिक्स एण्ड इकोनोमिक इण्डियाज फोरन पौलिसी," नई दिल्ली, 1994, पृ0 194
43. राजबाला सिंह-"भारत की विदेश नीति," जयपुर 2005, पृ0 64
44. बी. एल. फड़िया -"अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति," पृ0 321
45. नव भारत टाईम्स, 13 मार्च, 1983 नई दिल्ली।
46. हिन्दुस्तान टाईम्स, 28 नवम्बर, 1982 नई दिल्ली।
47. बी. एस. गहलोत-"भारतीय विदेश नीति," दिल्ली 2004 पृ0 76